

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 08 फरवरी, 2017

**विषय-** जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

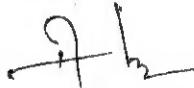
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-21/III-C/उ0रा0वि0से0प्रा0/2017 दिनांक 17.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत में शासनादेश सं0-24 एक(5)/छत्तीस(1)/2005-23 एक(5)/2005 दिनांक 09.11.2005 द्वारा सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-स्थायी लोक अदालत-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-2574/दस-98-24(8)92 लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 सपठित ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय

  
(आलोक कुमार वर्मा)  
सचिव

**संख्या- 42 /XXXVI(1)/ 2017-157/2016 तददिनांकित।**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव